11. Directorate of Transport, Delhi Administration has launched an awareness campaign about vehicular pollution, health hazards as well as maintenance fff procedures to control vehicular pollution.

12. The Government has started a programme of running batterly powered busts to minimise vehicular pollution and improve the embient air quality in congested areas of traffic.

13. Pilot scale trials have been initiated by the Delhi Transport Corporation for using Compressed Natural Gas (CNG) as fuel.

वन ग्रामों का राजस्व ग्रामों में परिवर्तित किया जाना

2887. **श्री कैलाश नारायण सारंग :** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो पश्चर प्रदेश के कितने वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित किए जाने के प्रस्ताव प्राप्त को हुए थे और अब तक कितने प्रस्ताओं स्वीकृति दी जा चुकी है ;

(ग) क्या यह सच है कि इन वन ग्रामों की स्थापना वन संरक्षण अधिनियम के लागें होने से पूर्व हो चुकी थी और इन अका गैर-वानिकी प्रयोजनों के लिए उपयोग भी उक्त अधिनियम के लागू किए जाने से पूर्व शुरू हो चुका था ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने अब उनके नियमितीकरण के लिए राज्य सरकार को अधिकृत किया है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) मध्य प्रदेश सरकार ने वन वन (संरक्षण), अधिनियम, 1980 के तहत 216 वन ग्रामों का राज्य ग्रामों में बदलने क लिए 10 प्रस्ताव भेजे हैं। इन सभी 10 प्रस्तावों में, राज्य सरकार, मे अनिवार्य ब्यौरे मांग गए हैं जिनकी अभी प्रतीक्षा है।

(ग) जी, हां।

(घ) वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में बदलने के लिए वन भूमि को औपचारिक रूप से उपयोग में लाने/अनारक्षित करने से पहले वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति लेनी होती है।

सरकार द्वारा रणथम्भौर बाघ परियोजना (टाइगर प्रोजेक्ट) के लिए धनराशि का दिया जाना

2888. **डा० अबरार अहमद :** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान 30 जून, 1992 तक केन्द्रीय सरकार ने रणथाम्भौर बाघ परियोजना के लिए मद-वार तथा वर्ष-वार कितनी धनराशि प्रदान की है क्या उसे वस्तुतः खर्च किया गया है ; यदि हां, तो मद-वार खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) क्या खर्च की गई धनराशि की लेखापरीक्षा (ऑडिट) कराई गई है ; यदि हां, तो क्या लेखापरीक्षक (आडिटर) ने कुछ आपत्तियां उठाई हैं, यदि हां, तो ये आपत्तियां क्या हैं और ये कब से लंबित हैं तथा क्या इससे पूर्ववर्ती अवधि की लेखापरीक्षा आपत्तियां भी लंबित हैं, यदि हां, तो उसके लिए कौन उत्तरदायी है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ: (क) और (ख) सूचना राजस्थान राज्य सरकार से एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।